



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]
No. 310]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जून 3, 1999/ज्येष्ठ 13, 1921
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 1999/JYAISTHA 13, 1921

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1999

का. आ. 414 (अ).—भारत सरकार की नई दूर संचार नीति, 1999 में यह उपबंध है कि भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण को, केन्द्रीय सरकार (अपनी अनुज्ञापक की हैसियत में) और किसी अनुज्ञप्तिधारी के बीच विवादों के समाधान के लिए माध्यस्थम् कृत्य समुद्देशित किए जाएंगे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुज्ञप्ति करार के अधीन या उसके संबंध में ऐसे मामलों के सिवाय, जिनके विनिश्चय के लिए दूर संचार सेवाओं के संबंध में अनुज्ञप्ति में कोई उपबंध विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, केन्द्रीय सरकार और अनुज्ञप्तिधारी के बीच उद्भूत किसी प्रश्न, विवाद या मतभेद की बाबत माध्यस्थम् कार्यवाही करने के कृत्य सौंपती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विवाद में के किसी विषय का निर्देश ऐसे विषय का अवधारण करने के लिए माध्यस्थम् हेतु भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

माध्यस्थम् कार्यवाहियां, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। माध्यस्थम् का स्थान नई दिल्ली में होगा।

[फाइल सं० : 845-51/98-एल० आर०]

गुरदीप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1999

S.O. 414 (E).—Whereas the New Telecom Policy 1999 of the Government of India provides that Telecom Regulatory Authority of India shall be assigned the arbitration function for resolution of disputes between Central Government (in its capacity as licensor) and any licensee;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby entrusts the function of conducting arbitration proceedings in respect of any question, dispute or difference arising between the Central Government and the licensee under the licence agreement or in connection therewith except in respect of the matters for decision of which any provision specifically provided under the licence relating to the telecommunication services.

Reference of any matter in a dispute to Telecom Regulatory Authority of India for arbitration to determine such matter, shall be made by the Central Government.

The arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) and the rules made thereunder. The venue of the arbitration shall be at New Delhi.

[F. No. 845-51/98-LR]

GURDIP SINGH, Jt. Secy.